कृषि विकास में विविधता, बंजर भूमि विकास और वृक्ष लगाना, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रक और ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, लघु और विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्र वृद्धि और आवास सुविधाओं का विस्तार योजना में दर्शाई गई रोजगार पर आधारित विकास नीति के मूल घटक हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष औसतन 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। यह अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बेरोजगारी का बैकलॉग लगभग 10 मिलियन होने की संभावना है जबकि योजना के आरम्भ में यह 17 मिलियन थी। प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अथवा शिक्षित/अशिक्षित युवा, जिन्हें आठवीं योजना के अंत में नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी और जो बेरोजगार रह जाएंगे, के संबंध में अलग अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

**आठवीं योजनावधि के दौरान जनता का सहयोग**

1845. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इसके प्रथम वर्ष के दौरान देश के 150 ब्लाकों में स्थानीय जनता के सहयोग से विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जून, 1992 तक उन सभी 150 ब्लाकों का पता लगा लिया है जहां, इन योजनाओं को आरम्भ किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग ऐसे ब्लाकों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन ब्लाकों में ये योजनाएं किस महीने से कार्यान्वित की जाएंगी?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम)** : (क) जी हां, आठवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान लोगों तथा जन संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी से माइक्रो स्तरीय सहभागिता आयोजना को 150 ब्लाकों में बतौर प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) स्कीमों को अगस्त, 1992 के मध्य तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा तथा ब्लाकों की पहचान की जाएगी। इसके बाद कार्यान्वयन शुरू होगा।

**गरीबी कम करने में विदेशी सहायता की विफलता**

1846. **श्री राम जेठमलानी** :
**श्री वीरेन जे० शाह** :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1992 के "दि इकानोमिक टाइम्स" में "फोरेन एड फेल्ड टु हैल्प इंडिया रिमूव पावर्टी, सेज स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित काटो संस्थान ने भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में पर्याप्त प्रगति न होने का आरोप लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है;

(घ) क्या इस अध्ययन प्रतिवेदन में केन्द्रीय योजनाओं में परिवर्तन करने के सुझाव भी दिए गए हैं; और